संघवाद को कमजोर करना: केंद्रीय वित्तपोषण, राज्य और शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को अस्वीकार करने के लिए तमिलनाडु के केंद्रीय हिस्से को रोकने के केंद्र सरकार के फैसले ने भारत में संघवाद और शिक्षा नीति पर गर्म बहस छेड़ दी है। यह प्रस्तुति इस कदम के निहितार्थों, केंद्र और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद, और भारत के शिक्षा प्रणाली में भाषा नीति और सहयोगात्मक संघवाद के व्यापक मुद्दों का पता लगाती है।

by OJAANK IAS

समग्र शिक्षा योजना

1

2018-19: योजना शुरू की गई

सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को एकीकृत किया गया।

2

उद्देश्य

सभी स्कूली बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

3

वर्तमान गतिरोध

तमिलनाडु ने 2,152 करोड़ रुपये के गैर-वितरण को चिह्नित किया, जिससे 40 लाख छात्रों और 32,000 कर्मचारियों को प्रभावित हुआ।

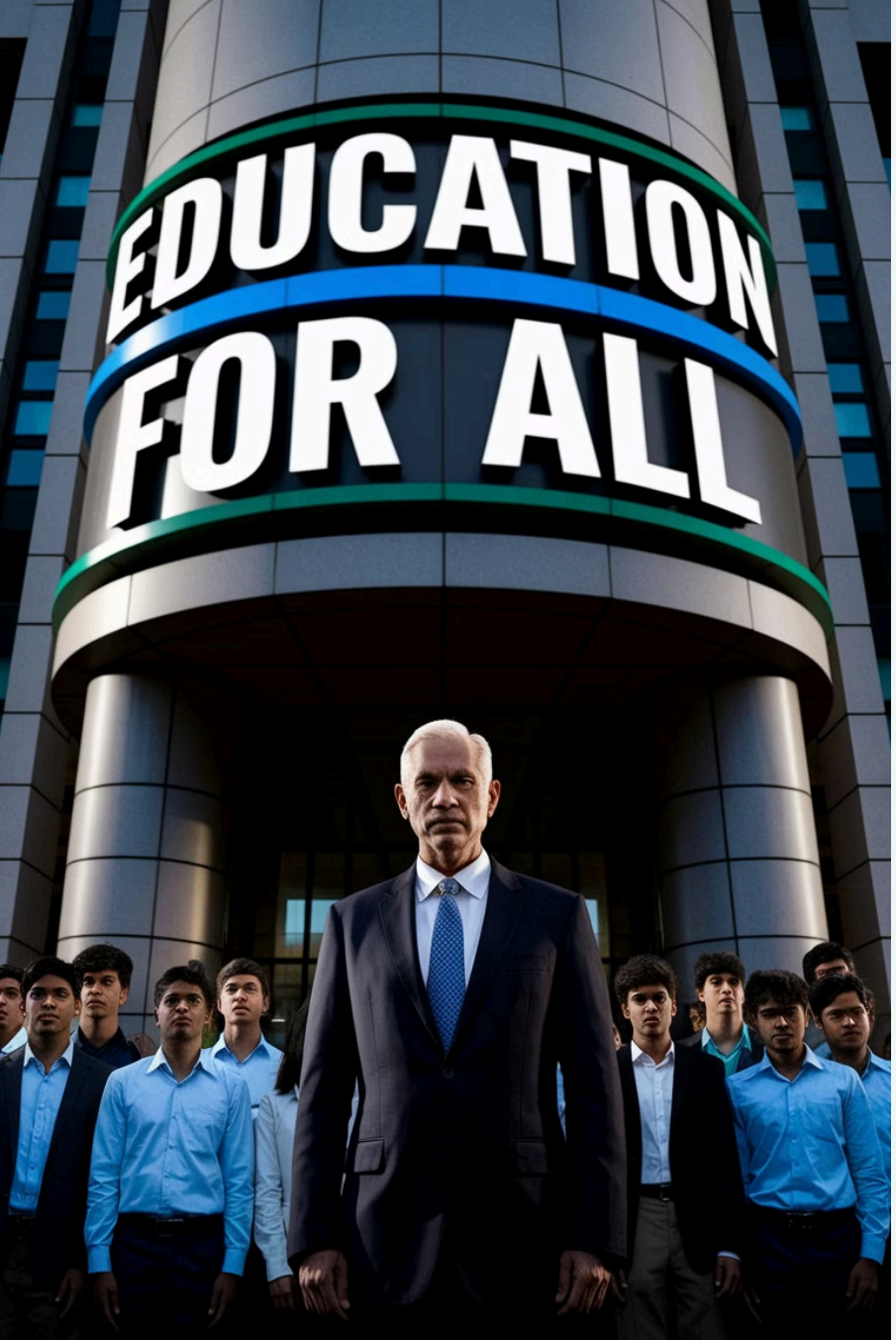

केंद्र का रुख

1 **धन रोका गया**

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि धन केवल तब जारी किया जाएगा जब तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति को "अक्षर और भावना" में लागू करेगा।

2 **भाषा नीति**

तीन-भाषा सूत्र को अपनाने पर जोर दिया: तमिल, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा।

3 **आरोप**

तमिलनाडु के नेतृत्व को विभाजनकारी और राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का आरोप लगाया।

Get full OJAANK 75 Days CHALLENGE #ANTIM PRAHAR Course from Ojaank App Now.

PRELIMS AB RUKEGA NAHI, 💯 Download the Ojaank app and purchase course 👍🏻

Course Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/517

COURSE FEATURE 👇🏻

तमिलनाडु का प्रतिक्रिया

भाषा नीति

1968 से तमिल और अंग्रेजी के द्विभाषी नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। त्रिभाषी प्रणाली का विरोध 1937 से है।

मुख्यमंत्री का रुख

एम.के. स्टालिन त्रिभाषी नीति के संवैधानिक आदेश पर सवाल उठाते हैं। बेहिचक दबाव के खिलाफ चेतावनी देते हैं।

प्रभाव

वित्तीय कमी से स्कूल शिक्षा बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ता है, जिससे लाखों छात्रों और कर्मचारियों को नुकसान होता है।

भाषा नीति का ऐतिहासिक संदर्भ

1

1937

तमिलनाडु का त्रिभाषीय प्रणाली के खिलाफ विरोध शुरू हो गया।

2

1968

तमिलनाडु ने तमिल और अंग्रेजी की द्विभाषीय नीति अपना ली।

3

2020

एनईपी (NEP) पेश की गई, जिससे भाषा नीति पर बहस फिर से छिड़ गई।

4

वर्तमान

भाषा नीति और एनईपी कार्यान्वयन को लेकर चल रहा विवाद जारी है।

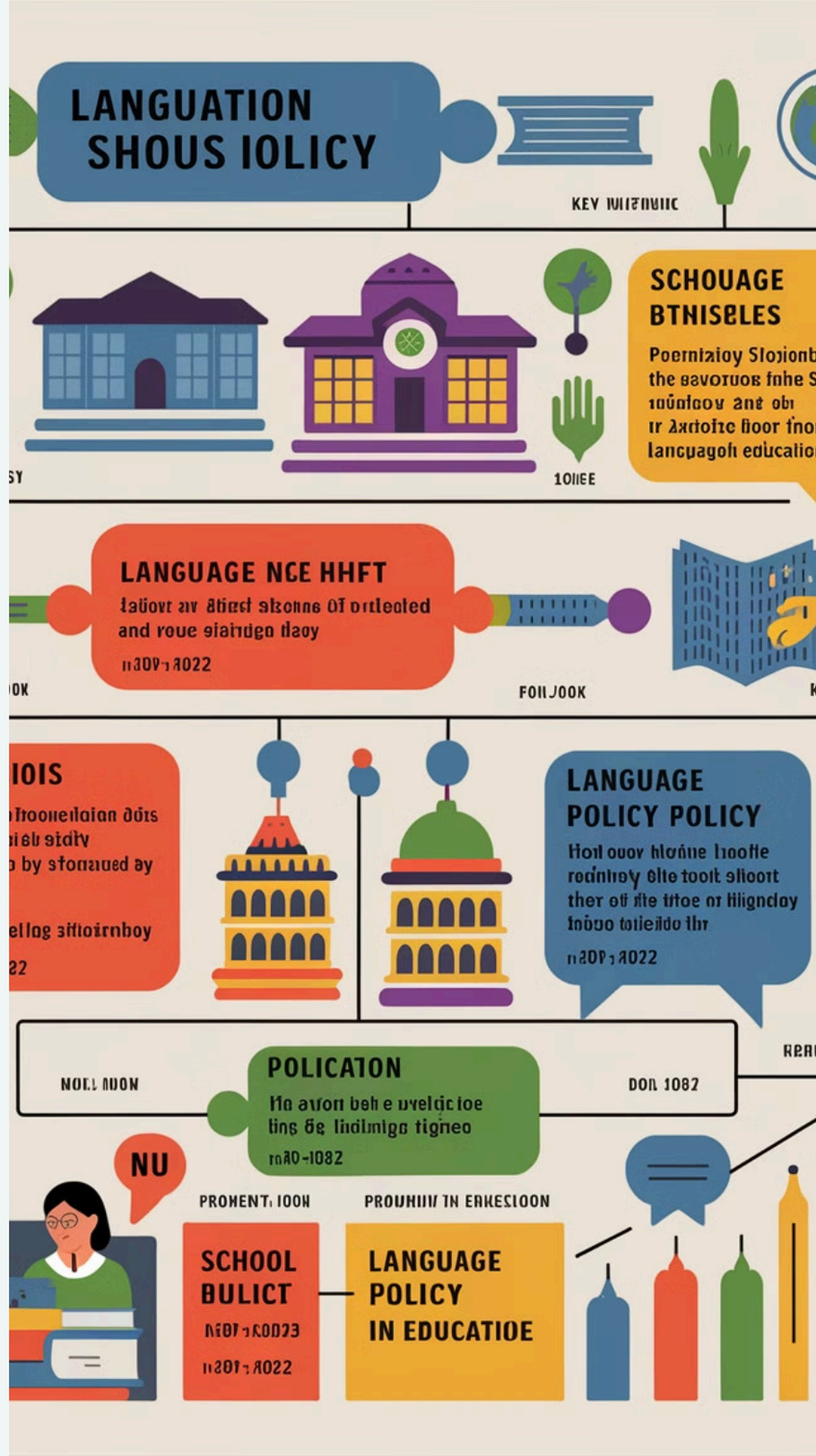

संवैधानिक विचार

समवर्ती सूची

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिसके लिए विविध क्षेत्रों में सफल कार्यान्वयन के लिए लचीलापन और संवाद की आवश्यकता होती है।

राज्य स्वायत्तता

अब तक, लगातार केंद्र सरकारों ने तमिलनाडु की भाषा नीति पर उसकी स्वायत्तता का सम्मान किया है।

सहकारी संघवाद

एक कठोर, एक-आकार-सभी-के-लिए दृष्टिकोण सहकारी संघवाद को कमजोर करने और राज्यों में असंतोष पैदा करने का जोखिम है।

Get full PIB AND ECONOMIC SURVEY RFR COMBO Course from Ojaank App Now.

आज ही Admission लें कल से फीस बढ़ जाएगी 👇🏻 👇🏻

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/515

संघवाद के लिए निहितार्थ

राज्य स्वायत्तता

धन रोकना शिक्षा नीतियों को निर्धारित करने के राज्यों के अधिकार को चुनौती देता है।

संवाद और लचीलापन

सफल कार्यान्वयन के लिए खुले संचार और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

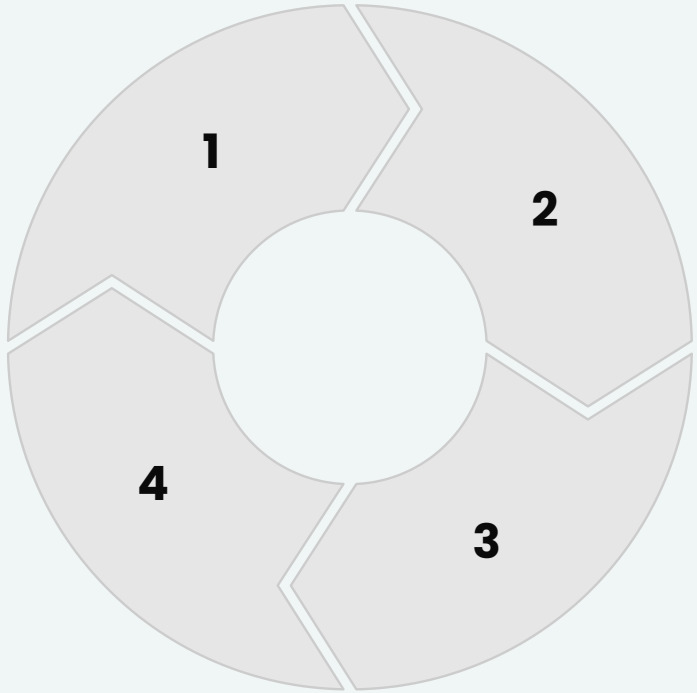

सहयोगात्मक संघवाद

कठोर दृष्टिकोण से असंतोष और सहयोग की कमजोरी हो सकती है।

नीति कार्यान्वयन

एक-आकार-सभी के दृष्टिकोण से विविध क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता।

प्रस्तावित समाधान

एनईपी से वित्त पोषण का विच्छेदन

समग्र शिक्षा और पीएम एसएचआरआई योजना वित्त पोषण को एनईपी कार्यान्वयन से अलग करें।

1

प्रदर्शन सूचकांक

विशिष्ट नीति अपनाने के बजाय सामान्य प्रदर्शन सूचकांकों से वित्त पोषण करें।

2

राज्य शिक्षा नीति

तमिलनाडु को अपनी लंबे समय से लंबित राज्य शिक्षा नीति को अंतिम रूप देना और लागू करना चाहिए जो एनईपी का एक व्यवहार्य विकल्प हो।

3

संवाद और समझौता

केंद्र और राज्यों के बीच खुले संवाद को प्रोत्साहित करें ताकि आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान खोजे जा सकें।

4

हितधारक और उनकी भूमिकाएं

केंद्रीय सरकार

राष्ट्रीय नीतियों का गठन करना, वित्तपोषण प्रदान करना, समान शिक्षा पहुंच सुनिश्चित करना।

राज्य सरकारें

नीतियों को लागू करना, स्कूलों का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को स्थानीय जरूरतों के अनुकूल बनाना।

छात्र और अभिभावक

प्राथमिक लाभार्थी, चिंताओं को व्यक्त करना, शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेना।

शिक्षक

भूमि पर नीतियों को लागू करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, शैक्षिक परिणामों को आकार देना।

निष्कर्ष: आगे का रास्ता

1 **संतुलित दृष्टिकोण**

राष्ट्रीय उद्देश्यों और शिक्षा नीति में राज्य स्वायत्तता का सम्मान करते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाएं।

2 **खुला संवाद**

चिंताओं को संबोधित करने और आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर संवाद को प्रोत्साहित करें।

3 **लचीली कार्यान्वयन**

विविध आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों के क्षेत्रीय अनुकूलन की अनुमति दें।

Follow Ojaank Sir

IAS with Ojaank Sir

Ojaank_Sir

IAS with Ojaank Sir

Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें

8285894079

8285894079